



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोर्प्र० रावालियर
ठिकानी - ३०२५०/२०१८/टीकमगढ़/अ०८
मीहन तिहं तनय श्री रुप सिंह ठाकुर

निवासी ग्राम बकपुरा तह. वजिला टीकमगढ़

• पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मोर्प्र० शासन

• प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अपर कोर्टर जिला टीकमगढ़ मोर्प्र० के
प्र० क्र० ०३ निग०/२०१५-१६ में पारित आदेश दिनांक २६/३/२०१८
केविस्त्र अंतर्गत धारा T 50 मोर्प्र० भ० ०२०८० म० १९५९

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

यह कि पुनरीक्षणकर्ता को ग्राम बकपुरा अंतर्गत तहसीलदार वजिला टीकमगढ़में ख.न. ५१४,५२० का विधिवत दखिल रद्दित भूमि के अंतर्गत प्र० क्र० ०७०/अ-१९४४/८५-८६ आदेश दिनांक १९/५/८६ के अनुसार किया गया था जिसकी इन्द्राजी इत्थतय इत्तलायबी पंजी ५ शासकीय आदेशों को अमल करने का रजिस्टर में अंकित कियागया था तत्पश्चात उक्त इत्तलायबी पंजी के आधार पर उक्त अमल राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाते जिसकी जिम्मेवारी तत्कालीन पटवारी की थी परंतु तत्कालीन पटवारी ने र राजस्वरिकार्डमें अमल नहीं किया जो पटवारी की भूमि रही है।

2. यह कि उक्त पटटा प्राप्ति के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता ने प्रश्नाधीन भूमि में ऐसी अपेक्षा करके उक्त भूमि में फसल उत्पादन कर अपनी आधिक स्थिति बढ़ा कर वर्ष 1999- एवं वर्ष 2000 में अपने परिवार में कुछ भूमिया कृप्य की जो समस्त परिवार में भूमि का रकवा वर्तमान में १०.७७ एकड़ हो गया है परंतु पटटा प्राप्ति दिनांक १८/३/८६ को समस्त भाइयों के परिवार में मात्र सभी के रकवा मिला कर ५.७८ एकड़ भूमि थी जो सभी भाइयों में पारिवारिक विभाजन के पश्चात २.०२ एकड़ से कम रकवा होने के कारण व्यवस्थापन किया गया था। नायब तहसीलदार स्मरा के द्वारा एक प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3024/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री डी.के. पासी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26-03-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पट्टा दिनांक को आवेदक व उसके परिवार के पास 5.83 हैक्टेयर भूमि धारित थी । जिस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के नाम का पट्टा खारिज किया जाकर भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्रह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सरकार</p> <p style="text-align: left;"><i>[Signature]</i> वीडर</p>	